

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 24 जुलाई, 1985

सं.ओ.वि./एफ.डी./70-85/35143.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़ (2) मै. मुख्य अभियन्ता, थर्मल प्लांट, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, फरीदाबाद के श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं/हैं, न्यायनिर्णय हेतु विनिर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री मनोहर लाल, लोको शन्टर ड्राईवर अपने पद पर रैगुलर होने एवं रुपये 700—1,250 के स्केल का हकदार बनता है ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

सं.ओ.वि./एफ.डी./77-85/31135.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़ 2. मुख्य अभियन्ता, थर्मल प्लांट, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, फरीदाबाद के श्रमिक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद के नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री ओम प्रकाश, लोको शन्टर ड्राईवर अपने पद पर रैगुलर होने एवं रुपये 700—1,250 के स्केल का हकदार बनता है । यदि हां तो किस विवरण में ।

कुलबन्त सिंह,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम एवं रोजगार विभाग ।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 23 जुलाई, 1985

सं.ओ.वि./रोहतक/97-85/30760.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० महेश्वरी कम्पनी मार्फत एच०एन०जी० एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, बहादुरगढ़ रोहतक, के श्रमिक श्री देव प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री देव प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?